(ख) इस संबंध में पौड़ी गढ़वाल जिले की कितनी ग्राम सभाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) अभ्यावेदनों के संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) इस मामले में पौड़ी गढ़वाल जिले से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Joint ventures with foreign firms in the leather industry

*233. SHRI MATANG SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering several proposals with foreign firms for joint ventures in the leather industry;

(b) if so, the details of each of such proposals; and

(c) the progress made in this regard and the anticipated foreign investment in the leather industry during the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

*234. (Transferred to 22nd March, 1993)

गुजरात में हैंडपम्पों का लगाया जाना

*235. गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में अब तक जिलेवार और केन्द्रवार कितने-कितने हैंडपम्प लगाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उतमभाई एच० पटेल) : (क) गुजरात राज्य सरकार ने ग्रामीण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाने के लिए 1992–93 में कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। तथापि, केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य सरकार ने डा० बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी कार्यक्रम के भाग के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में 2127 हैंडपम्प लगाने के लिए 5.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए 5 अगस्त, 1991 के पत्र द्वारा अनुरोध किया था।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बस्तियों की संख्या और अपेक्षित हैंडपम्पों की संख्या के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	जिले का नाम	बस्तियों की संख्या	अपेक्षित हैंडपम्पों की संख्या
1.	बड़ौदा	120	188
2.	पंचमहल	244	436
3.	भड़ौच	102	163
4.	सूरत	93	161
5.	बलसाड़	700	1179
		1264	2127

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में पेयजल सुविधाएं सुलभ कराने के लिए आबंटित की गई 60 करोड़ रुपये की कुल राशि में से

राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। बाद में राज्य सरकार ने आबंटित राशि में ही साबरकंठा जिले में 339 हैंडपम्प लगाए जाने वाली 229 बस्तियों और बनासकंठा जिले में 82 हैंडपम्प लगाए जाने वाली 62 बस्तियों को शामिल कर लिया था।

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत जनवरी, 1993 तक लगाए गए हैंडपम्पों की संख्या के जिला-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

क्रमांक	जिले का नाम	लगाए गए हैंडपम्पों की संख्या
1.	बड़ौदरा	70
2.	पंचमहल	190
3.	सूरत	40
4.	भड़ौच	61
5.	बलसाड़	304
6.	साबरकंठा	153
7.	बनासकंठा	37
	योग :	855

Shortage of Vitamin 'C'

236. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a chronic and continuing shortage of Vitamin 'C' formulations and multi vitamin preparations containing vitamin 'C' for the last several months;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government propose to allow import of Vitamin 'C' at concessional rate of custom duty;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) what other steps Government proopse to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Supply of bulk Vitamin C had got dislocated during the second and third quarters of 1992 due to shortfall in production of one of the two units. The position has since improved and, as per the available information, the present production level is adequate to meet the estimated demand.

(c) to (e) At present there is no proposal to reduce the customs duty on Vitamin C. Government, however, is keeping a constant watch and in case the situation so warrants, duty reduction would be considered in the consumer interest.

Development of a substitute for timber

SHRI MOHAMMED SALIM: SHRI M. A. BABY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a meet on developing substitutes for timber was held recently in the Capital;

(b) whether efforts to develop a substitute for timber as industrial and construction sector material would get adequate support; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Policy Advisory Group on Wood Substitution of the